

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 27, शुक्रवार, शके 1944-नवम्बर 18, 2022 <i>Kartika 27, Friday, Saka 1944- November 18, 2022</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (बजट) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 18, 2022

जी.एस.आर.100 :-राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम सं. 8) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) नियम, 2022 है।

(2) ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) “अधिनियम” से राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम सं. 8) अभिप्रेत है;

(ii) “लाइन विभाग” से नोडल विभाग से भिन्न सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है; और

(iii) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किंतु परिभाषित नहीं किये गये किंतु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः समनुदिष्ट किया गया है।

अध्याय-2

अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के लिए रकम का निश्चित किया जाना और स्कीमों को तैयार किया जाना

3. अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के लिए रकम का निश्चित किया जाना.- राज्य सरकार का वित्त विभाग अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.)

और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) में रखी जाने वाली कुल रकम के लिए वित्तीय वर्ष के लिए पृथक् आदेश जारी करेगा।

4. स्कीमों को तैयार किया जाना और उनका अनुमोदन.- (1) अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए स्कीमों प्रस्तावित करते समय, विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करेंगे, अर्थात्:-

- (i) विशिष्ट रूप से दुर्बल जनजाति समूह;
- (ii) अनुसूचित क्षेत्र;
- (iii) उपांतरित क्षेत्र विकास एप्रोच; और
- (iv) क्लस्टर एप्रोच।

(2) अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) के लिए स्कीमों प्रस्तावित करते समय, विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करेंगे, अर्थात्:-

- (i) विशिष्ट रूप से दुर्बल अनुसूचित जाति समूह; और
- (ii) क्लस्टर एप्रोच।

(3) अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए प्रस्तावित स्कीमों संबंधित निधियों के प्रयोजन के साथ निर्धारित होंगी और नवाचारों तथा उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों का समर्थन करेंगी जो लक्षित हिताधिकारियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता के सुधार में सहायक होंगी। निधियां नयी अवसंरचना और संस्थानों के सृजन के लिए उपयोग की जा सकेंगी। तथापि, संस्थाओं को चलाने या अवसंरचना के रख-रखाव के लिए आवर्ती खर्च अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) से निधिबद्ध नहीं किये जायेंगे।

(4) यदि कोई प्रतिबद्ध व्यय है जिसे पिछले वित्तीय वर्ष से अग्रणीत किये जाने की आवश्यकता है, तो इसे वार्षिक योजना में सम्मिलित किया जायेगा और अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के अधीन समर्थित किया जायेगा।

(5) नोडल विभाग, लाइन विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। लाइन विभागों के प्रस्ताव निम्नलिखित से मिलकर बनेंगे,-

- (i) प्रत्येक स्कीम के उद्देश्यों, आवश्यकता निर्धारण, मुख्य परिणाम क्षेत्रों को स्पष्ट करने वाला एक टिप्पण और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर विभिन्न उप-समूहों के मध्य विकास के बारे में परिमाणात्मक सूचक;
- (ii) चल रही स्कीमों के मामले में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की परिमाणात्मक शब्दों में भौतिक और वित्तीय प्रगति;
- (iii) कार्य-वार ब्यौरों सहित प्रस्तावित स्कीम के लिए भौतिक और वित्तीय प्रक्षेपक और मापने योग्य मुख्य परिणाम क्षेत्र और जहां आवश्यक हो, मुख्य संपादन सूचक; और
- (iv) स्कीम के लिए मद-वार बजट का अलग-अलग विवरण।

(6) नोडल विभाग लाइन विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा करेगा और यह समाधान होने के पश्चात् कि वे अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुकूल हैं, उन्हें मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए संबंधित सशक्त समिति के समक्ष रखेगा।

(7) नोडल विभाग सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को सहमति के लिए वित्त (व्यय) विभाग को भेजेगा/अग्रेषित करेगा।

अध्याय-3

संस्थागत व्यवस्थाएं

5. राज्य परिषदें.- (1) अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित राज्य अनुसूचित जाति विकास परिषद् (रा.अ.जा.वि.प.) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

(i)	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
(ii)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रभारी मंत्री	सदस्य
(iii)	मुख्य सचिव	सदस्य
(iv)	वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(v)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य-सचिव
(vi)	आयोजना विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(vii)	राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य	सदस्य

(2) अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित राज्य अनुसूचित जनजाति विकास परिषद् (रा.अ.ज.जा.वि.प.) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

(i)	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
(ii)	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का प्रभारी मंत्री	सदस्य
(iii)	मुख्य सचिव	सदस्य
(iv)	वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(v)	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य-सचिव
(vi)	आयोजना विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(vii)	राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य	सदस्य

(3) राज्य अनुसूचित जाति विकास परिषद् (रा.अ.जा.वि.प.) और राज्य अनुसूचित जनजाति विकास परिषद् (रा.अ.ज.जा.वि.प.) सेक्टर विशेषज्ञों, सिविल सोसायटी सदस्यों, समुदाय प्रतिनिधियों और अन्य पणधारियों को विशेष आमंत्रितों के रूप में परिषदों में आमंत्रित कर सकेंगी। तथापि, विशेष आमंत्रितों की संख्या संबंधित परिषद् के कुल सदस्यों के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विभाग, जिसकी कार्यसूची पर चर्चा होनी है, का प्रभारी सचिव भी उपस्थित होगा।

6. राज्य परिषदों के कृत्य.- राज्य परिषदें, अधिनियम की धारा 6 के अधीन उनको समनुदेशित किये गये कृत्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात्:-

- अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के अधीन की गयी विभिन्न पहलों की उचित योजना पर सलाह;
- अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों पर सलाह; और

- (iii) अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के उचित कार्यान्वयन के लिए उठाये जाने वाले कदमों/किये जाने वाले अध्यापार्यों पर सलाह।

7. राज्य परिषदों की बैठकें.- (1) की गयी पहल की प्रगति को मानिटर करने के लिए राज्य परिषदों की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(2) परिषद् का सदस्य-सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से, कार्यसूची के साथ परिषद् की बैठक की लिखित सूचना कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व जारी करेगा।

(3) अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को सात दिन की सूचना देकर परिषद् की विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी।

(4) परिषद् अपनी बैठकों में कार्य संचालन करते समय प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुसरण करेगी जैसे कि विहित किये जायें।

(5) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी अन्य सदस्य द्वारा की जायेगी।

8. सशक्त समितियां.- (1) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित सशक्त समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(iii)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रभारी शासन सचिव	संयोजक
(iv)	स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(v)	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(vi)	आयोजना विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(vii)	लोक निर्माण विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(viii)	स्वायत्त शासन विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(ix)	महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(x)	कृषि विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य

(2) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित सशक्त समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(iii)	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का प्रभारी शासन सचिव	संयोजक
(iv)	स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(v)	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(vi)	आयोजना विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(vii)	लोक निर्माण विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(viii)	स्वायत्त शासन विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(ix)	महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(x)	कृषि विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य

(3) सशक्त समितियों के अध्यक्ष किसी अन्य लाइन विभागों, जिनकी कार्यसूची पर चर्चा की जानी है, के प्रभारी सचिव को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं।

(4) संबंधित नोडल विभाग संबंधित सशक्त समिति की, उनकी शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कृत्यों का पालन करने में सहायता करेगा।

9. सशक्त समितियों के कृत्य.- संबंधित सशक्त समिति, अधिनियम की धारा 8 के अधीन उन्हें समनुदेशित किये गये कृत्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

- (i) सशक्त समिति, अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्कीमों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए लाइन विभागों से प्रस्तावों में ऐसे परिवर्तनों के लिए सिफारिश कर सकेगी जैसे कि आवश्यक समझे जायें; और
- (ii) नोडल विभाग और लाइन विभागों को फीडबैक उपलब्ध करवायेगी।

10. नोडल विभाग के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सहायता इकाई.- राज्य सरकार, नोडल विभागों को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समनुदेशित कार्यों के निर्वहन के लिए तकनीकी सहायता इकाई के साथ समुचित रूप से मजबूत करेगी। संबंधित नोडल विभाग अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के संबंध में क्रियाकलापों की योजना और मानिट्रिंग के लिए तकनीकी सहायता इकाई में संबंधित क्षेत्र में स्थायी अधिकारी या विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय-4

विविध

11. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) नोडल विभाग, वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग-वार उपलब्धियों और अनुपयोजित निधियों को अंतर्विष्ट करते हुए, स्कीमों के क्रियान्वयन के परिणाम पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे सशक्त समिति के समक्ष रखेगा।

(2) सशक्त समिति वार्षिक रिपोर्ट की संवीक्षा करेगी और उसे अनुमोदित करेगी, सशक्त समिति से अनुमोदन के पश्चात्, नोडल विभाग वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा।

[सं. एफ.4(40)वित्त-1(1)/आ.व्य./2022]

राज्यपाल के आदेश से,

रोहित गुप्ता,
शासन सचिव।

FINANCE (BUDGET) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, November 18, 2022

G.S.R.100 .-In exercise of the powers conferred by section 12 of the Rajasthan State Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Fund (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Act, 2022 (Act No. 8 of 2022), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

Chapter-I
Preliminary

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan State Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Fund (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(i) “Act” means the Rajasthan State Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Fund (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Act, 2022 (Act No. 8 of 2022);

(ii) “Line Departments” means any department of the Government other than the nodal department; and

(iii) “Section” means section of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

Chapter-II

Earmarking of amount for Scheduled Castes Development Fund and Scheduled Tribes Development Fund and Preparation of Schemes

3. Earmarking of amount for the Scheduled Castes Development Fund and the Scheduled Tribes Development Fund.- The State Government in the Finance Department shall issue a separate order for the financial year for the total amount to be kept in the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF).

4. Preparation of Schemes and their Approval.- (1) While proposing the schemes for the Scheduled Tribes Development Fund (STDF), departments shall focus on the following, namely:-

(i) Particularly Vulnerable Tribal Groups;

(ii) Scheduled Areas;

(iii) Modified Area Development Approach; and

(iv) Clusters Approach.

(2) While proposing the schemes for the Scheduled Castes Development Fund (SCDF), departments shall focus on the following, namely:-

(i) Particularly Vulnerable Scheduled Caste Groups; and

(ii) Clusters Approach.

(3) The schemes proposed for the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF) must be aligned with the purpose of the

respective funds and shall support innovations and high impact areas which shall help in improving the overall quality of life of target beneficiaries. The funds may be used for creating new infrastructure and institutions. However, the recurring cost for running institutions or maintaining the infrastructure shall not be funded from the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF).

(4) If there is any committed expenditure which needs to be carried forward from the last financial year, it shall be included in the annual plan and supported under the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF).

(5) The Nodal Department shall invite proposals from the line departments. The proposals of the line departments shall consist of,-

- (i) a note explaining the objectives of each scheme, need assessment, key result areas, and quantifiable indicators pertaining to development among various sub-groups within the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
- (ii) physical and financial progress of previous financial year in case of ongoing schemes in quantifiable terms;
- (iii) physical and financial projections for the proposed scheme with work-wise details and measurable key result areas and key performance indicators, wherever necessary; and
- (iv) item wise budget break-up for the scheme.

(6) The Nodal Department shall scrutinize the proposals received from the line departments and after satisfying that they are in consonance with the provisions of the Act and these rules and place them before the Empowered Committee, concerned for evaluation and approval.

(7) The Nodal Department shall send/forward the proposals approved by the Empowered Committee to the Finance (Expenditure) Department for concurrence.

Chapter-III **Institutional Arrangements**

5. State Councils.-(1) The State Scheduled Castes Development Council (SSCDC) constituted under section 5 of the Act shall consist of:-

(i)	Chief Minister	Chairperson
(ii)	Minister in-charge of Social Justice and Empowerment Department	Member
(iii)	Chief Secretary	Member
(iv)	Secretary to the Government in-charge of Finance Department	Member
(v)	Secretary to the Government in-charge of Social Justice and Empowerment Department	Member Secretary
(vi)	Secretary to the Government in-charge of Planning Department	Member
(vii)	Three members representing the Scheduled Castes in the State Legislature nominated by the State Government	Member

(2) The State Scheduled Tribes Development Council (SSTDC) constituted under section 5 of the Act shall consist of:-

(i)	Chief Minister	Chairperson
(ii)	Minister in-charge of Tribal Area Development Department	Member
(iii)	Chief Secretary	Member
(iv)	Secretary to the Government in-charge of Finance Department	Member
(v)	Secretary to the Government in-charge of Tribal Area Development Department	Member Secretary
(vi)	Secretary to the Government in-charge of Planning Department	Member
(vii)	Three members representing the Scheduled Tribes in the State Legislature nominated by the State Government	Member

(3) The State Scheduled Castes Development Council (SSCDC) and State Scheduled Tribes Development Council (SSTDC) may invite sector experts, civil society members, community representatives and other stakeholders as special invitees to the councils. However, the number of special invitees shall not be more than thirty percent of the total members of the respective Council. The Secretary in-charge of Department whose agenda is being discussed will also be present.

6. Functions of States Councils.- The State Councils shall, in addition to functions assigned to them under section 6 of the Act, perform the following functions, namely:-

- (i) Advice on proper planning of different initiatives under the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) or Scheduled Tribes Development Fund (STDF), as the case may be;
- (ii) Advice on priority areas for implementation of the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) or Scheduled Tribes Development Fund (STDF), as the case may be; and
- (iii) Advice on steps / measures to be taken for proper implementations of the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) or Scheduled Tribes Development Fund (STDF), as the case may be.

7. Meetings of State Councils.-(1) State Councils shall meet at least once in a financial year to monitor the progress of the initiatives.

(2) The Member Secretary of the Council shall, with the approval of Chairperson, issue a written notice of the Meeting of the Council along with agenda at least fifteen days in advance.

(3) Special Meeting of the Council may be called by the Chairperson by giving notice of seven days to the members.

(4) The Council shall follow such rules of procedure while transaction business at its meetings as may be prescribed.

(5) In absence of the Chairperson, the meeting of the Council shall be presided over by any other member nominated for the purpose by the Chairperson.

8. Empowered Committees.- (1) The Empowered Committee constituted under section 7 of the Act for development of the Scheduled Casts shall consist of the following, namely:-

(i)	Chief Secretary	Chairperson
(ii)	Secretary to the Government in-charge of Finance Department	Member
(iii)	Secretary to the Government in-charge of Social Justice and Empowerment Department	Convener
(iv)	Secretary to the Government in-charge of School Education Department	Member
(v)	Secretary to the Government in-charge of Rural Development and Panchayati Raj Department	Member
(vi)	Secretary to the Government in-charge of Planning Department	Member
(vii)	Secretary to the Government in-charge of Public Works Department	Member
(viii)	Secretary to the Government in-charge of Local Self Government Department	Member
(ix)	Secretary to the Government in-charge of Women and Child Development Department	Member
(x)	Secretary to the Government in-charge of Agriculture Department	Member

(2) The Empowered Committee constituted under section 7 of the Act for development of the Scheduled Tribes shall consists of the following, namely:-

(i)	Chief Secretary	Chairperson
(ii)	Secretary to the Government in-charge of Finance Department	Member
(iii)	Secretary to the Government in-charge of Tribal Area Development Department	Convener
(iv)	Secretary to the Government in-charge of School Education Department	Member
(v)	Secretary to the Government in-charge of Rural Development and Panchayati Raj	Member

	Department	
(vi)	Secretary to the Government in-charge of Planning Department	Member
(vii)	Secretary to the Government in-charge of Public Works Department	Member
(viii)	Secretary to the Government in-charge of Local Self Government Department	Member
(ix)	Secretary to the Government in-charge of Women and Child Development Department	Member
(x)	Secretary to the Government in-charge of Agriculture Department	Member

(3) The Chairperson of the Empowered Committees may invite Secretary in-charge of any other line departments, whose agenda is being discussed, as Special Invitees.

(4) The respective Nodal Department shall assist the respective Empowered Committee to perform its functions and exercise its powers.

9. Functions of Empowered Committees.- The respective Empowered Committee shall, in addition to functions assigned to them under section 8 of the Act, perform the following functions, namely:-

- (i) The Empowered Committee may recommend for changes in the proposals to the line departments as deemed necessary to enhance the impact of the schemes for the welfare of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be; and
- (ii) Provide feedback to the nodal department and line departments.

10. Administrative and Technical Support Unit for the Nodal Department.- The State Government shall appropriately strengthen the respective nodal department by empowering them with Technical Support Unit for performing the assigned tasks as per the provisions of the Act. The respective nodal department may appoint permanent officer or specialist in respective field in Technical Support Unit for planning and monitoring of activities with respect to the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF).

Chapter-IV Miscellaneous

11. Annual Report.- (1) The Nodal Department shall prepare the Annual Report on the outcome of the implementation of the schemes containing department-wise achievements and the unutilized funds during the financial year and place it before the Empowered Committee.

(2) The Empowered Committee shall scrutinise the Annual Report and approve the same, after approval from the Empowered Committee, the Nodal Department shall place the Annual Report before the State Legislature.

[No. F.4(40)FD-1(1)/Budget/2022]

By order of the Governor,

**ROHIT GUPTA,
SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.